विचार बिन्दु

संसार के विरुद्ध खड़े रहने के लिए शक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ईसा दुनिया के खिलाफ खड़े रहे, बुद्ध भी अपने जमाने के खिलाफ गए, प्रहलाद ने भी वैसा ही किया। ये सब नम्रता के धनि थे। अकेले खड़े रहने की शक्ति नम्रता के बिना असंभव है। –महात्मा गाँधी

सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत का बड़ा कदम

भारत बहुत लंबे समय से सेमीकंडक्टर का उत्पादक बनने के प्रयासों में लंबे समय से लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन का क्षेत्र अत्यंत मुश्किल है जिसमें उतरने के लिये किये गए प्रयासों में कई धक्के भी लगे हैं। चालीस साल पहले 1980 के दशक में मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लगने से भारत की शुरुआती महत्वाकांक्षी शुरुआत को ऐसा झटका लगा जिससे उबरने में इतना समय लग गया। बाद में 2000 के दशक में, भारत फिर मौका चूक गया जब इंटेल के प्रस्तावित मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को हासिल करने में वह नाकाम रहा। इस तरह दिसंबर 2021 में जब केंद्र सरकार के 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' शुरू करने किया तब भी आशंका बनी रही क्योंकि वेदांता–फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर टूट गया था। बात तब बनती फिर नज़र आई जब माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के साणंद में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी बनाने के लिए 2.7 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान किया। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ इसलिए अहम था कि यह भारत का पहला बड़े पैमाने का कमर्शियल सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट था, बल्कि इसलिए भी कि यह एक जानी–मानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी से आया था। पॉलिसी बनाने वालों और इंडस्ट्री पर नज़र रखने वालों के लिए, यह एक बड़ी कामयाबी थी। नीतियों और इनके क्रियान्वयन पर निगाह रखने वालों के अनुसार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, ऐलान अधिक मायने नहीं रखते, अमल मायने रखते हैं। अब, जब माइक्रोन का साणंद प्लांट कमर्शियल ऑपरेशन में जा रहा है, तो स्वाभाविक ही ऐलान असलियत में बदल रहा है। फिर भी यह संदेह भी बना हुआ है कि क्या यह प्रोजेक्ट ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भारत के लिये जगह बना पायेगा और क्या यह आगे के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकेगा?

माइक्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की लीडिंग मेमोरी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है। इसकी साणंद फैसिलिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बैकएंड स्टेज पर काम करती है, जहां फैब्रिकेशन प्लांट में बनाए गए वेफर्स को कस्टमर्स को भेजने से पहले असेंबल, टेस्ट और पैक किया जाता है। भारत की यह पहली हाई–वॉल्यूम मेमोरी असेंबली और टेस्ट साइट है। जहां पांच लाख स्क्वायर–फुट का क्लीनरूम दुनिया भर में सबसे बड़ा सिंगल रेज़्ड–फ्लोर सेमीकंडक्टर असेंबली क्लीनरूम है। इसे क्रिटिकल एरिया में क्लास 1,000 स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, जो मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरी प्रिसिजन और कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। साणंद प्लांट के लिए, वेफ़र्स माइक्रोन के ग्लोबल फ़ैब्रिकेशन नेटवर्क से लिए जाएंगे। बाद में भारत में ही वेफ़र थिनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और मॉड्यूल बनाये जाएंगे। इसे 'वेफ़र–इन से फ़िनिश्ड–प्रोडक्ट–आउट प्रोसेस' कहते हैं। यहां पर्सनल कम्प्यूटर, स्मार्टफ़ोन, डेटा सेंटर और स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए डीआरएएम और एनएएनडी उत्पाद बनाये जाएंगे। ये उत्पाद न केवल नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में ग्लोबल कस्टमर्स को सेवा देंगे, साथ ही घरेलू सप्लाई को भी मज़बूत करेंगे। बताया गया है कि पूरी तरह से तैयार होने के बाद, साणंद फ़ैसिलिटी से माइक्रोन के ग्लोबल पैकेजिंग और टेस्ट आउटपुट का लगभग दस प्रतिशत काम हो जाने की उम्मीद है। यह प्लांट दिखाता है कि एडवांस्ड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग ऑपरेशन ग्लोबल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड का पालन करते हुए भारत अपनी क्षमता बना सकता है। इसीलिए भारत के सेमीकंडक्टर पुश पर निगाह रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि माइक्रोन का ऑपरेशनल प्लांट देश के लिये एक ज़रूरी क्रेडिबिलिटी का संकेत देता है।

वास्तव में जून 2023 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की घोषणा के बाद से ही इसका असर दिखने लगा था। यह असर इस बात से स्पष्ट है कि उसके बाद सात और ओसेट परियोजनाओं को मंज़ूरी मिलीहै। कई पाइपलाइन में हैं। विशेषज्ञ हालांकि, वह चेतावनी भी देते हैं कि इस क्षेत्र में भविष्य के इन्वेस्टमेंट इस बात पर निर्भर करेंगे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पैकेजिंग और टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को कैसे और कितनी प्राथमिकता देता है। जहां तक फैब्स की बात है, किसी देश में पैकेजिंग फैसिलिटी होने का मतलब यह नहीं है कि फैब्स अपने आप अपना काम शुरू कर देंगे। फिर भी, यह बात कि माइक्रोन का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन तक आगे बढ़ गया है, इससे लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को दूर करने में मदद मिली है। इस प्रोजेक्ट ने भारत इस सोच को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है कि देश एक हाई–एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन देने के लिये तैयार है।

> **माइक्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की लीडिंग मेमोरी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है। इसकी साणंद फैसिलिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बैकएंड स्टेज पर काम करती है, जहां फैब्रिकेशन प्लांट में बनाए गए वेफर्स को कस्टमर्स को भेजने से पहले असेंबल, टेस्ट और पैक किया जाता है। भारत की यह पहली हाई-वॉल्यूम मेमोरी असेंबली और टेस्ट साइट है। जहां पांच लाख स्क्वायर-फुट का क्लीनरूम दुनिया भर में सबसे बड़ा सिंगल रेज़्ड-फ्लोर सेमीकंडक्टर असेंबली क्लीनरूम है।**

विशेषज्ञ मानते हैं कि हालांकि यह अभी एक स्ट्रेटेजिक असरहै, और उसे कैपेसिटी वाला असर बनना है। वे मानते हैं कि माइक्रोन का सबसे बड़ा असर, कम से कम शुरुआत में, इंडस्ट्रियल के बजाय साइकोलॉजिकल अधिक हो सकता है, जिसकी आवश्यकता भी है। भारत में ऑपरेशन शुरू करने वाला यह कदम ग्लोबल मेमोरी लीडर ताइवान, कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य की कंपनियों को भारत में अपने रिस्क के अंदाज़ों को फिर से देखने पर मजबूर करेगा और उनके आगे कदम उठाने की झिझक कम होगी क्योंकि इससे रियल टाइम में भारत की पॉलिसी की विश्वसनीयता की परख होती है। हालांकि, सिर्फ़ संकेत देने भर से आगे के इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं मिलेगी। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में आम तौर पर 15 से 20 साल के कमिटमेंट होते हैं, जिसका मतलब है कि कंपनियों को हेडलाइन इंसेंटिव से कहीं ज़्यादा पॉलिसी स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। भारत के नीति निर्माताओं से अपेक्षा होगी कि माइक्रोन की साणंद परियोजना एक स्टैंड अलोन आउटपोस्ट बनकर न रह जाय, बल्कि एक एंकर इन्वेस्टमेंट बने और यह लगातार पॉलिसी कंटिन्यूटी और इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर निर्भर करेगा। क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान काम नहीं है इसलिए माइक्रोन का प्लांट चालू होने के बाद भी, देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर निर्भर करेगी। उसके लिये चौबीसों घंटे भरोसेमंद बिजली, पानी की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। सपोर्टिंग सप्लायर्स की मौजूदगी भी उतनी ही ज़रूरी होगी, जिसमें सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरर्स, मटीरियल कंपनियां और इक्विपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हैं, जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ के साथ को–लोकेट कर सकें। सबसे अहम है एक स्किल्ड वर्कफोर्स की पाइपलाइन और एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज़, जिनमें हेटेरोजिनस इंटीग्रेशन शामिल है। इसके लिए एक रोडमैप भी बहुत ज़रूरी है।

जानकारों का कहना है कि माइक्रोन का साणंद प्रोजेक्ट भारत के सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के कुछ हिस्सों को जरूर वैलिडेट करता है, लेकिन केवल इससे पूरी बात नहीं बनेगी, क्योंकि बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे असेंबली और टेस्टिंग, में वेफर फैब्रिकेशन की तुलना में कम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। माइक्रोन का प्रोजेक्ट दिखाता है कि एक कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल ज़ोन के अंदर, भारत सेमीकंडक्टर टाइमलाइन के हिसाब से भरोसेमंद बिजली, पानी, ज़मीन तक पहुंच और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन दे सकता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता को लेकर पहले के संदेह दूर हो जाते हैं। फिर भी ढांचागत रिस्क बने हुए हैं। कई राज्यों में ऐसी स्थितियों को दोहराना, बढ़ते इंडस्ट्रियल लोड के तहत बिजली की ग्रिड स्टेबिलिटी मजबूत करना, एक सप्लायर इकोसिस्टम बनाना और भविष्य के फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए तैयारी करना, अगली चुनौतियां होगी। भारत को एशिया के चिप हब के साथ अपने अंतर को कम करना होगा। भले ही भारत बैकएंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपने पहले कदम उठा रहा है, फिर भी यह एशिया के स्थापित सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स से बहुत पीछे है। मलेशिया, चीन और जापान जैसे देशों ने पैकेजिंग फर्मों, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल सप्लायर्स और स्पेशलाइज्ड लेबर पूल्स में फैले इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने में दशकों लगाए हैं। उनके फायदों को हमारे यहां जल्दी से दोहराया नहीं जा सकता। मलेशिया में, हालांकि सरकारी कंट्रोल और चीन के लिए बैकडोर होने की चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक अनुभवी प्लेयर होने का उसे फायदा है। जापान टेक्नोलॉजी में लीडर है, खासकर जब सप्लाई चेन की बात आती है। मगर वह फैब टेक के साथ नहीं चल पाया है और कुछ हद तक उसकी बढ़ती उम्र और घटती आबादी की वजह से उनके पास टैलेंट की भी कमी है। चीन के पास टेक्नोलॉजी, टैलेंट और पैसा सब कुछ है। हालांकि, दुनिया भर में उस पर भरोसे की कमी उसके लिये एक नेगेटिव बात है। ऐसे में इन देशों की तुलना में, भारत के फायदे सामने आ रहे हैं।

यहां टैलेंट एक ऐसा एरिया है जहां प्रोग्रेस पहले से ही दिख रही है। माइक्रोन की साणंद फैसिलिटी में लगभग 1,300 कर्मियों में से लगभग 700 गुजरात और आस–पास के राज्यों के नए कॉलेज ग्रेजुएट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल और मटीरियल इंजीनियरिंग के इन ग्रेजुएट ने भारत में ऑपरेशन्स को सपोर्ट करने के लिए मलेशिया और सिंगापुर की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 3–6 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग पूरी की है। हालांकि, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और सप्लाई चेन डेप्थ बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। भारत के लिए समय के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मटीरियल सप्लायर, पैकेजिंग सबस्ट्रेट और स्पेशल इक्विपमेंट सर्विस प्रोवाइडर का एक लोकल इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी होगा। जियोपॉलिटिकल विंडो की भी बात आती है। भारत को बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से भी फ़ायदा हो सकता है। चीन के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी रीअलाइनमेंट के बीच, मल्टीनेशनल कंपनियां सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए डाइवर्सिफ़िकेशन स्ट्रेटेजी पर तेज़ी से विचार कर रही हैं। इससे भारत को एक पोटेंशियल ओपनिंग मिलसकती है। हालांकि आज भी भारत के फ़ायदे इकोसिस्टम के बजाय पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स से ज़्यादातर प्रभावित हैं। माइक्रोन के साणंद प्लांट ने भारत को एक ज़रूरी क्रेडिबिलिटी थ्रेशहोल्ड पार करने में मदद की है। उस क्रेडिबिलिटी को सप्लायर्स, टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक गहरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में बदलना अगली असली मुश्किल चुनौती होगी।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

प्रगति की नई रफ्तार : विकसित राजस्थान का संकल्प हो रहा साकार

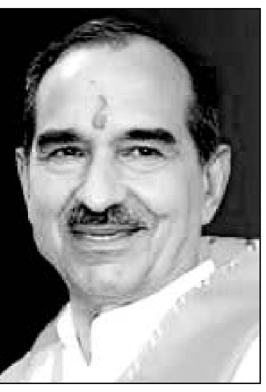

मदन राठौड़

राजस्थान दिवस के अवसर पर जारी आंकड़े प्रदेश की विकास यात्रा का ठोस दस्तावेज है। यह आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अल्प समय में ही पकड़ी प्रगति की नई रफ्तार से विकसित राजस्थान का संकल्प साकार हो रहा है। इनकी तुलना पिछली सरकार के कार्यकाल से की जाती है, तो अंतर केवल संख्याओं के साथ ही दृष्टिकोण, कार्यसंस्कृति और परिणामों में भी स्पष्ट नजर आता है।

वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया। यही कारण है कि अनेक योजनाओं में राजस्थान देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पहुंचा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी होना इस बात का प्रमाण है कि किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने में राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। पोषण–कुपोषण योजना के कंपोनेंट–ए एवं सी के सफल क्रियान्वयन ने सामाजिक क्षेत्र में भी सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने तकनीक और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। कृषि विभाग की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, किसानों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण में तेजी और पारदर्शिता जैसे कदम पूर्ववर्ती सरकार की धीमी कार्यप्रणाली से स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं।

पर ड्रॉप – मोर क्रॉप योजना के तहत 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और किसानों की आय बढ़ाने का भी मजबूत माध्यम बना है। पशुपालन क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का प्रमाण है कि राज्य को डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की योजनाओं में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। धरती आबा जनभागीदारी अभियान में 'बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट' है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफलता पाई है।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले 5 वर्षों (2018–2023) की तुलना में वर्तमान सरकार के लगभग 25 माह (2024–2026) के कार्यकाल में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ी है पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल प्रशिक्षण के तहत 2.35 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, वर्तमान सरकार ने मात्र लगभग 25 महीनो में 3.41 लाख को प्रशिक्षित किया गया। कृषि क्षेत्र में पहले 29,430 फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) बनाए गए थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 35,368 हो चुकी है।

ऊर्जा और सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले 13,160 सोलर पंप स्थापित किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर 16,864 हो गई है। पर ड्रॉप–मोर क्रॉप जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन स्थापित कर जल प्रबंधन को नई दिशा दी है।

ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले जहां केवल 1,478 गांव इससे जुड़े थे, वहीं अब यह आंकड़ा 41,037 गांवों तक पहुंच गया है। पहले 1,104 गांव सड़कों से जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1,717 हो गई है। मनरेगा के तहत सृजित मानव दिवसों में तो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पहले जहां 22,597 लाख मानव दिवस सृजित हुए थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 98,894 लाख मानव दिवस तक पहुंच गया है।

ढाणियों के विद्युतीकरण में पहले 3,952 कार्य हुए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 8,261 हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत जहां पहले 2,92,507 घरों को नल कनेक्शन मिले थे, वहीं अब यह बढ़कर 3,14,530 हो चुका है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जहां 489 स्वयं सहायता समूह सक्रिय थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2,911 हो गई है।

प्रशासनिक सुधारों से जहां पहले केवल 986 पट्टों का वितरण हुआ था, वहीं वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 88,724 तक पहुंचा दिया है।

कृषि कनेक्शन के क्षेत्र में पहले 21,136 कनेक्शन दिए गए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 41,820 हो गई है। उच्च शिक्षा में जहां पहले केवल 5 महाविद्यालय स्थापित हुए थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 21 हो गई है।

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपखंड कार्यालय भवन निर्माण में पहले मात्र 57 भवन बने थे, अब यह संख्या बढ़कर 185 हो गई है। सड़क निर्माण में पहले 10.36 हजार किमी, अब 11.31 हजार किमी निर्माण हुआ है व राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले 1,517 किमी, अब 2,294 किमी निर्माण हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले जहां 10 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 18 हो गई है। स्कूल अपग्रेडेशन में पहले 113 करोड़ रुपये, अब 403 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पुलिस थानों के अपग्रेडेशन में पहले जहां केवल 57 कार्य हुए थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2,064 हो गई है।

आंकड़ों का यह अन्तर शासन की कार्यशैली का परिणाम है। पिछली सरकार पर अक्सर धीमी निर्णय प्रक्रिया, भ्रष्टाचार के आरोप और योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई के आरोप लगते रहे, वहीं वर्तमान सरकार ने गुड गवर्नेंस और डिलीवरी को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर उनकी संवेदनशीलता और समझ अधिक गहरी है। यही कारण है कि योजनाएं कागजों से बाहर निकलकर खेतों और गांवों तक पहुंच रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन भी इस प्रगति का एक बड़ा कारण है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में राजस्थान की अग्रणी भूमिका यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से विकास को नई गति मिलती है। राजस्थान में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि विकास अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। अल्प समय में ही अनेक क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि यह संकेत देती है कि विकसित राजस्थान 2047 का सपना साकार हो रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने जो कार्य संस्कृति स्थापित की है, वह तेज होने के साथ ही परिणामोन्मुखी भी है। यही कारण है कि राजस्थान आज अपने अतीत की विरासत पर गर्व कर रहा है और अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है।

–मदन राठौड़, राज्यसभा सदस्य।

ईरान युद्ध : ऊर्जा संकट के साए में तीसरे महायुद्ध की दहलीज पर विश्व व्यवस्था

डॉ. योगेश शर्मा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन का वह कालजयी कथन आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की धुरी बना हुआ है कि राष्ट्रों के न तो कोई शाश्वत मित्र होते हैं और न ही शाश्वत शत्रु, केवल उनके हित ही शाश्वत होते हैं और उनका अनुसरण करना ही परम कर्तव्य है। वैश्विक राजनीति के इस यथार्थवादी धरातल पर राष्ट्रीय हित, शक्ति–संतुलन और रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। यही कारण है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, टकराव और सहयोग के नए–नए रूप समय–समय पर उभरते रहते हैं। मध्य पूर्व में 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद उत्पन्न स्थिति इसी परिवर्तनशील और हित–आधारित राजनीति का एक अत्यंत जटिल और खतरनाक उदाहरण है, जो न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि संपूर्ण वैश्विक भू–राजनीतिक स्थिरता को एक अभूतपूर्व संकट की ओर धकेलती प्रतीत हो रही है।

पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व का इतिहास गवाह है कि यहाँ भूगोल ही भाग्य का निर्धारक रहा है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर स्थित यह क्षेत्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के बीच एक ऐसी भू–राजनीतिक स्थिति रखता है, जहाँ से वैश्विक व्यापार की धमनियां गुजरती हैं। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, बाब–एल–मंदेब और स्वेज नहर जैसे समुद्री मार्ग पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा हैं।

शीत युद्ध के दौर से ही यह क्षेत्र अमेरिका और सोवियत संघ की शक्ति–प्रतिस्पर्धा की रणभूमि बना रहा है। इज़राइल और अरब देशों के बीच भू–क्षेत्र और पहचान को लेकर चलने वाले संघर्षों ने यहाँ की मिट्टी को कभी शांत नहीं होने दिया। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति में शाह पहलवी के पश्चिम समर्थक शासन के पतन के बाद अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक कट्टर अमेरिका–विरोधी राज्य के रूप में उभरा। तेहरान में 52 अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखने की घटना ने संबंधों में जो कड़वाहट पैदा की, उसकी गूँज आज भी सुनाई देती है।

2026 का यह वर्तमान युद्ध आधुनिक संघर्ष का एक नया और विनाशकारी स्वरूप लेकर आया है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला किया, तो शुरुआती चरण में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने की खबरों ने पश्चिम को यह विश्वास दिलाया कि यह युद्ध शीघ्र ही उनके पक्ष में निर्णायक रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत निकली। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान को इस प्रकार के हमले का पूर्वानुमान था और उसने पहले से ही एक बहुस्तरीय तथा विकेंद्रित सैन्य रणनीति तैयार कर रखी थी। शीर्ष नेतृत्व पर हुए प्रहार के बावजूद ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया अधिक संगठित और व्यापक होकर सामने आई। विशेष रूप से हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को बाधित करने की ईरान की धमकी ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। विश्व की ऊर्जा आपूर्ति के इस प्रमुख मार्ग पर रोक की आशंका मात्र से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई हैं। ईरान की रणनीति ने एक व्यापक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए खाड़ी देशों सहित मध्य पूर्व के अन्य संवेदनशील बुनियादी ढाँचों को भी निशाना बनाना शुरू किया है। इसका स्पष्ट उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगियों पर युद्धविराम के लिए वैश्विक स्तर पर मनोवैज्ञानिक दबाव और एक गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न करना है।

इस संघर्ष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम यह है कि नाटो देश, जो सामान्यतः अमेरिका के सबसे विश्वसनीय सहयोगी माने जाते हैं, इस बार ईरान संकट पर एकमत नहीं हैं। रूस–यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस प्रकार यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को व्यापक सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की थी, वैसी एकजुटता यहाँ नदारद है। यूरोपीय देशों का एक बड़ा और प्रभावशाली वर्ग इस बात पर जोर दे रहा है कि इस संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी भी इस संघर्ष में खुलकर समर्थन देने से बचते दिखाई दे रहे हैं।ये देश भली–भांति जानते हैं कि यह संघर्ष उस क्षेत्र में हो रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता का केंद्र है। कोई भी व्यापक सैन्य टकराव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर ऐसी रणनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है जिससे उबरना दशकों तक संभव नहीं होगा।

ईरान और अमेरिका के बीच इस लंबे टकराव का एक बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी रहा है। 2015 में हुआ परमाणु समझौता (JCPOA), जिसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार करने का वादा किया था, लेकिन 2018 में अमेरिका के इस समझौते से बाहर होने के निर्णय ने क्षेत्र में तनाव की एक नई लहर पैदा कर दी। पिछले कुछ वर्षों में अब्राहम समझौते (JCPOA) , के माध्यम से इज़राइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण और 22 (भारत, इज़राइल, अमेरिका और यूएई) जैसे समूहों के गठन से एक नए आर्थिक मॉडल की उम्मीद जगी थी।लेकिन वर्तमान युद्ध ने इन सभी नई भू–राजनीतिक संरचनाओं की सीमाओं और उनकी नाजुकता को उजागर कर दिया है।

इस संघर्ष के बीच प्रत्येक राष्ट्र अत्यंत सावधानी और संतुलन के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है, जो उनकी रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है।चीन, जो ईरान के तेल का एक प्रमुख आयातक है और जिसके साथ उसके दीर्घकालिक ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचागत समझौते हैं, ने प्रत्यक्ष टकराव से बचने की नीति अपनाई है। रूस ने भी अपने भू–राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए अब तक बहुत ही सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया दी है। भारत के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति यहाँ कसौटी पर है। एक ओर भारत के अमेरिका और इज़राइल के साथ मजबूत रणनीतिक और तकनीकी संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान और मध्य पूर्व के साथ उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा आधारित संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह, जिसे भारत ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुँच के लिए एक रणनीतिक द्वार के रूप में विकसित किया था, इस युद्ध और कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वर्तमान में शिथिलता का शिकार हो गया है।

निष्कर्षतः, यह पूरा घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईरान का यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसने वैश्विक राजनीति को एक अत्यंत जटिल और अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लगातार बढ़ रहे ऊर्जा संकट से आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, शेयर बाजार और सोना–चांदी की कीमतों में निरंतर अस्थिरता ने नए भूआर्थिक संकट को जन्म दिया है। परमाणु संयंत्र पर हमले से रेडियो एक्टिव रिसाव के खतरे और परमाणु युद्ध की आशंका मात्र ही इस युद्ध की भयावह तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए काफी है। इस संघर्ष ने संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रभावहीनता को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर दिया है।

युद्ध के दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैंऔर हर क्षण इस युद्ध में कुछ नवीनतम जुड़ता जा रहा है। यदि अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटता है, तो महाशक्ति वाली छवि पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग सकता है। वहीं यदि वह इस संघर्ष को और आगे बढ़ाता है, तो यह विश्व को एक व्यापक और दीर्घकालिक युद्ध में धकेल सकता है। इस बार यदि तीसरा महायुद्ध हुआ तो निश्चित ही परमाणु क्षमताओं से संपन्न राष्ट्रों के युद्ध से संपूर्ण विश्व व्यवस्था का विनाश निश्चित है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अतीत में दो महायुद्ध भी लंबे समय तक चले प्रतिशोध और तनाव के वातावरण से जन्मे थे और वर्तमान ईरान संकटभी वही कहानी कहता हुआ प्रतीत हो रहा है जहां किसी राष्ट्र की तरफ से जरा सी भी चूक विश्व को तीसरे महायुद्ध के गर्त में डाल सकती है।

–डॉ. योगेश शर्मा,
(लेखक संवैधानिक अध्येता और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं)

राशिफल मंगलवार 25 मार्च, 2026

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2083, मृगशिरा नक्षत्र सायं 5:33 तक, सौभाग्य योग रात्रि 03:09 तक, वणिज करण दिन 1:50 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

गृह स्थितिः सूर्य–मीन, चन्द्रमा–मिथुन, मंगल–कुम्भ, बुध–कुम्भ, गुरू–मिथुन, शुक्र–मीन, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सायं 5:33 तक है। राजयोग दिन 1:50 तक रहेगा। आज भद्रा दिन 1:50 से रात्रि 12:49 तक रहेगी। आज से दुर्गा पूजा (बंगाल में) आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ अमृत सूर्योदय से 9:31 तक, शुभ 11:02 से 12:33 तक, चर 3:35 से 5:05 तक, लाभ 5:05 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:30, सूर्यास्त 6:36

मेष
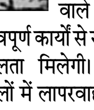

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

वृष
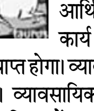

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी।

मिथुन
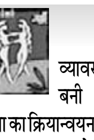

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कर्क

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

सिंह
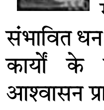

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनारहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या
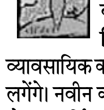

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेंगी।

वृश्चिक

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु
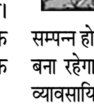

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

मकर
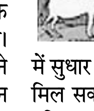

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।